

साप्ताहिक

न्यूज क्राइम फाइल

मुल्य- 02 रूपये

ग्वालियर, भिंड, मुरैना, छतरपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, खिखनी, जबलपुर, रीवा, सतना, होशंगाबाद, हरदा एवं इंदौर में प्रसारित।

कावड़ यात्रियों का पुष्प-वर्षा कर किया स्वागत

कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के साथ होगी माकूल व्यवस्थाएँ : मुख्यमंत्री



उदय प्रताप सिंह चौहान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ अनुकूल व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को उज्जैन त्रिवेणी शनिमंदिर से कावड़ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कावड़ यात्रियों का पुष्प-वर्षा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कावड़ का पूजन कर कावड़ उठाई और अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर संत श्री उत्तम स्वामी के साथ पैदल चलकर कावड़ यात्रा का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी त्यौहार उत्साह के साथ मनाने की परम्परा राज्य सरकार ने शुरू की है। ईश्वर और संतजन के आशीर्वाद से उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियाँ तेजी से की जा रही है। हम इस सोच के साथ सभी तैयारियाँ कर रहे हैं कि वर्ष-2028 के बाद यदि प्रतिवर्ष सिंहस्थ जैसे आयोजन हों तो किसी प्रकार की समस्या न आये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत उज्जैन में संतों के लिये आश्रम और अन्य व्यवस्थाओं को जुटाने के लिये सिंहस्थ धार्मिक सिटी का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिये सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया जल का महत्व

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कावड़ यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में कई संस्कृतियाँ हैं, दुनिया में तो 194 देश हैं लेकिन कोई देश अपने कोई भी शुभ काम प्रारंभ करने के लिए जल के माध्यम से कोई संकल्प नहीं लेता है। भारतीय संस्कृति जल ही जीवन की संस्कृति और जीवन जीने की पद्धति रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ईश्वर की कृपा से हम हजारों सालों से जल के गुणों से परिचित हैं। कावड़ यात्रा में विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, श्री सतीश मालवीय, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, श्री संजय अग्रवाल, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, श्री तपन भौमिक और संतों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

साइकिल से मिलेगी रफ्तार - स्कूल समय पर पहुंचने में होगी आसानी

शासन की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत कमला नेहरू सांदीपनि कन्या विद्यालय, भोपाल में आयोजित निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम में जब विद्यार्थियों को साइकिलें प्राप्त हुईं, तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। निःशुल्क साइकिल प्राप्त होने पर वे अत्यंत प्रसन्न हैं और इसके लिए म.प्र. शासन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टीलाखेड़ी की कक्षा 9वीं की छात्रा कुमारी रिया भारती ने मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, अब हमें स्कूल समय पर पहुंचने में आसानी होगी। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। इसी विद्यालय की कुमारी पूजा खन्ना ने कहा कि पैदल विद्यालय पहुंचने में अधिक समय लगता था, अब मैं 10 मिनट में विद्यालय पहुंच जाऊंगी। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। कुमारी सिमरन गौर ने भी निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार माना। कुमारी सिमरन ने कहा कि निःशुल्क साइकिल प्राप्त होने से जीवन में रफ्तार प्राप्त हुई है। अब हम आत्मविश्वास के साथ विद्यालय जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि कोई भी विद्यार्थी केवल साधन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना से विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनेंगे, समय की बचत होगी तथा उनकी उपस्थिति में भी सुधार आएगा। उन्होंने छात्र-छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें परिश्रम और लगन के साथ अध्ययन करने की प्रेरणा दी। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क वितरण योजना न केवल विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करती है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है। छात्राओं ने कहा कि वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा चलाई जा रही इस लोकहितकारी एवं दूरदर्शी पहल के लिए उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं।





पीडब्ल्यूडी मंत्री बोले-सड़कें रहेंगी तब तक गड़दे होते रहेंगे

राकेश सिंह ने कहा- गड़दे न हों ऐसी तकनीक नहीं

न्यूज क्राइम फाइल

मध्य प्रदेश में खराब सड़कों के निर्माण और सड़कों के गड़दों को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं आई है, जिसके आधार पर कह सकें कि ऐसी सड़क बनाएंगे जिस पर कभी गड़दा होगा ही नहीं। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड़दे होते रहेंगे। गलत तब है जब चार साल तक खराब न होने वाली सड़क में छह माह में ही गड़दे हो जाएं। राकेश सिंह ने कहा कि जो कुछ हम कर रहे हैं, प्रयास वही हो सकते हैं। मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है, जिसमें गड़दा होता ही नहीं। ऐसी कोई तकनीक अभी पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। उन्होंने सड़कों की खराब हालत और गड़दों के कारण होने वाली दिक्कतों के सवाल पर कहा कि सवाल ऐसा हो जिसका हम उत्तर दे सकें। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड़दे होते रहेंगे।

छह माह में गड़दे हो जाएं तो कार्रवाई होनी चाहिए-
राकेश सिंह

मंत्री राकेश सिंह ने यह भी कहा कि अगर कोई सड़क ऐसी है जिसको चार साल तक खराब नहीं होना चाहिए और छह महीने में गड़दे हो गए तो यह गलत है। ऐसे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान उस जमीन को लेकर भी सवाल हुए जिस पर सड़क बनाई जा रही है।

दूसरे राज्यों में 5 साल तक सड़कें चलती हैं तो एमपी में क्यों नहीं

मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि वर्क कल्चर बेहतर बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिटुमिन अब स्थानीय स्तर पर नहीं खरीदा जा सकेगा। भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम से ही खरीदा जाएगा। हमने उसे कंडीशन में डाल दिया है। जब बिटुमिन निकलेगा तो डिजिटल लॉक के साथ निकलेगा। जिस क्षेत्र के लिए बिटुमिन जाएगा वहां के सब इंजीनियर के मोबाइल पर ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद ही

डिजिटल लॉक खुलेगा और बिटुमिन अनलोड किया जा सकेगा।

एक से दो किलोमीटर की दूरी में रिचार्ज बोर बनाए जाएंगे

मंत्री सिंह ने कहा कि अगर किसी सड़क की फोटो लोकपथ एप में डाल दी गई और वह लोक निर्माण विभाग की नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग होती है। हमने तय किया है कि अगर पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं है तो शिकायतकर्ता को बताएंगे कि यह सड़क पीडब्ल्यूडी की नहीं है। अब एक से दो किलोमीटर की दूरी में रिचार्ज बोर बनाए जाएंगे ताकी सड़क का पानी बोर में जा सके। लोक कल्याण सरोवर भी बनाने का काम किया जाएगा। सारे चीफ इंजीनियर दस-दस लोक कल्याण सरोवर का निरीक्षण करेंगे। मैं भी खुद बीस स्थानों पर जाकर निरीक्षण करूंगा। लोक निर्माण विभाग मंत्री ने कहा कि भोपाल के ऐशबाग पुल में 90 डिग्री नहीं 119 डिग्री का टर्न है। इसमें सेफ्टी मेजर का पालन नहीं हुआ है तो कार्रवाई भी हुई है। इसमें राजस्व का नुकसान हुआ है। इसके पहले कभी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इंदौर में जिस पुल को लेकर मीडिया में बात आई है वह 114 डिग्री का है, लेकिन टर्निंग रेडियस 15 मीटर की बजाय 20 मीटर है जो ठीक है और यहां कोई राजस्व नुकसान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश भर के निर्माणाधीन पुलों की रिपोर्ट बुला रहे हैं। एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर रहे हैं ताकी कहीं से कोई बात आए तो उसका समाधान हो सके। हर माह में दो बार लोक निर्माण विभाग की सड़कों का औचक निरीक्षण होता है। इन्हें पता नहीं होता है कि कहां निरीक्षण के लिए जाना है।

कांग्रेस के कहने से सरकारें नहीं चलतीं ने विकास कार्य होते

जबलपुर में बनाए जा रहे फ्लाई ओवर को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कहने से सरकारें नहीं चलतीं और कांग्रेस के कहने से विकास कार्य नहीं होते। अभी उसमें लाइटिंग का काम बाकी है और जब यह काम पूरा हो जाएगा तो इसका लोकार्पण समय पर होगा, अभी काम बाकी है। इस फ्लाई ओवर को देखने दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं।

प्रोत्साहन



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को इंदौर में एक बगिया मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया।

थाना कमला नगर पुलिस ने निकाला सोनू एंजेल का जुलूस, कई दिनों से था फरार

न्यूज क्राइम फाइल

राजधानी भोपाल की कमला नगर थाना पुलिस ने हत्या का प्रयास के मामले में फरार शातिर अपराधी सोनू एंजेल उर्फ तरुण पाल को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही गुरुवार को कमला नगर थाना पुलिस ने आरोपी का कमला नगर में पैदल जुलूस भी निकाला है। सोनू एंजेल के विरुद्ध पूर्व में थाना शाहपुरा हबीबगंज कोलार वा टीटी नगर में करीब 21 मामले दर्ज हैं।

यह है पूरा मामला

थाना कमला नगर में 18 जनवरी 2025 को फरियादी प्रशांत डोंगरे पिता अशोक डोंगरे निवासी अंबेडकर नगर ने सोनू एंजेल के विरुद्ध सख्खद दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार फरियादी ने बताया की सोनू एंजेल पुरानी रंजिश को लेकर गंदी गंदी गाली देकर छूरी से प्रशांत के साथ मारपीट की इसके बाद थाना कमला नगर ने मामले को गंभीरता से लेकर आरोपी सोनू



एंजेल के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की आरोपी तभी से फेरारी काट रहा था। 9 जुलाई को मुखबीर सूत्र से पुलिस ने घेराबंदी कर सोनू उर्फ एंजेल को गिरफ्तार कर लिया।

थाना प्रभारी निरूपा पांडे की रही अहम भूमिका

आरोपी को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका कमला नगर थाना प्रभारी निरूपा पांडे की रही। थाना प्रभारी निरूपा पांडे ने टीम गठित कर आरोपी की तलाश में टीम में लगा रखी थी।



बिजली कंपनियों में 50 हजार पदों पर भर्ती होगी

एमपी में 35 लाख किसानों का 84 करोड़ रुपए टैक्स, ब्याज और पेनल्टी माफ

न्यूज क्राइम फाइल

मोहन यादव कैबिनेट ने पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में 49 हजार 263 नए पदों को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद तीनों कंपनियों में नियमित पदों की संख्या 77,298 हो जाएगी। इससे कंपनियों के काम और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार आएगा, तो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या घटेगी। वर्तमान संविदा कर्मचारियों की सेवाएं भी यथावत रहेंगी। कैबिनेट ने 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ कर दी है। सरकार किसानों से उड़द और मूंग खरीदने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। केंद्र ने अभी कम मात्रा में खरीदी की मंजूरी दी थी, जिसे बढ़ाया जाएगा।

बिजली कंपनियों में इन पदों पर होगी भर्ती

सहायक यंत्री - 211 पद
जूनियर इंजीनियर - 1339 पद
लाइन सहायक - 8094 पद
लाइन परिचारक - 20, 118 पद
बाकी भर्तियां अन्य पदों पर की जाएगी
भोपाल की होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को लेकर फैसला

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि सरकार ने राजधानी के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को डिजाइन करने और निर्माण के साथ उसके संचालन, हस्तांतरण के आधार पर पीपीपी मोड पर सौंपने को मंजूरी पहले ही दी थी। अब यह तय किया गया है कि लीज के पंजीयन और



स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) विभागीय बजट से की जाएगी। निवेश संवर्धन (इन्वेस्टमेंट प्रमोशन) के लिए यह तय किया गया है कि जो भी डेवलपर आएगा उसे प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी।

प्रदेश के 35 लाख किसानों को सरकार से बड़ी राहत

प्रदेश के 35 लाख किसानों पर कृषि सिंचाई जलकर के ब्याज और पेनल्टी के 84.17 करोड़ रुपए बकाया हैं। जल संसाधन विभाग लगातार तकादा लगा रहा था। अब सरकार ने तय किया है कि किसानों से यह राशि नहीं ली जाएगी। कैबिनेट ने राशि माफ करने की मंजूरी दे दी है। यह योजना साल 2026 तक रहेगी और सभी किसानों को एक साल में मूलधन की राशि जमा

करने का मौका मिलेगा। सन 2000 से आज तक 25 साल में कृषकों पर सिंचाई जलकर की मूल राशि 563.29 करोड़ बकाया है। इसमें पेनाल्टी और ब्याज राशि 84 करोड़ 17 लाख है। कैबिनेट के फैसले के बाद एक अप्रैल 2025 तक की कुल बकाया जलकर राशि एकमुश्त जमा करने की सुविधा मिलेगी। यदि किसान उनके बकाया सिंचाई जलकर की मूल राशि एकमुश्त 31 मार्च 2026 तक जमा करते हैं तो दांडिक ब्याज की राशि माफ की जाएगी।

कैंपा फंड में मिले 1478 करोड़, नए कामों को मंजूरी

वन विभाग की प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैंपा फंड) की वार्षिक कार्ययोजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने

1478.38 करोड़ रुपए सहित कैंपा फंड से किए जाने वाले कामों को मंजूरी दी है। एमपी की वन भूमि के डायवर्जन के बाद पहले यह राशि भारत सरकार को मिलती है और बाद में केंद्र सरकार राज्य को यह राशि देती है। इस राशि से पौधारोपण, बिगड़े वनों का सुधार, नदियों के पुनर्जीवन, वन सीमा से लगे गांवों में बांस आदि पौधों का रोपण, ग्रामीणों की क्षमता-विकास, नगर वनों को तैयार करने जैसे काम किए जा सकेंगे।

मूंग-उड़द की ज्यादा खरीदी के लिए केंद्र को पत्र लिखेंगे

प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी के लिए सरकार की सिक्क्योरिटी, नुकसान की प्रतिपूर्ति और रबी सीजन 2024-25 में टारगेट से ज्यादा खरीदी गई ग्रीष्मकालीन मूंग की स्वीकृति पर कैबिनेट में चर्चा के बाद फैसला किया गया। इस दौरान 20 लाख टन मूंग खरीदी की संभावना है। भारत सरकार से 3.51 लाख मीट्रिक टन खरीदी की मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने तय किया है कि भारत सरकार को पत्र लिखा जाए कि 8.57 लाख मीट्रिक टन खरीदी की मंजूरी केंद्र की ओर से दी जाए।

मूल्य सूचकांक स्टॉप अधिनियम संशोधन विधेयक मंजूर

कैबिनेट में भारतीय स्टॉप अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 1 (क) के अंतर्गत अधिनियम के अनुच्छेदों में संशोधन के लिए भारतीय स्टॉप (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 को कैबिनेट मंजूरी दी गई है। मूल्य सूचकांक के इस संशोधन विधेयक से राज्य सरकार को 212 करोड़ का राजस्व मिलेगा।

भोपाल में विवाहिता ने फांसी लगाकर किया सुसाइड

पति बोला दूसरे युवक से बात करते रंगे हाथ पकड़ा था

न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल के कोलार इलाके में महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना शुक्रवार तड़के 3:30 बजे की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। पति ने पत्नी पर दूसरे युवक से प्रेम प्रसंग होने के आरोप लगाए हैं। सुसाइड से पहले पति और पत्नी के बीच दूसरे युवक से बात करने को लेकर विवाद भी हुआ था। जानकारी के मुताबिक मुस्कान पति अनिल (24) निवासी सर्वधर्म ए सेक्टर गृहिणी थी। मृतका के पति अनिल ने बताया कि शादी के सात साल बाद भी दोनों की कोई संतान थी। पति का आरोप है कि पत्नी दूसरे युवक से फोन पर बात करती थी। उसके साथ पूर्व में



भागने का प्रयास कर चुकी थी। हालांकि तब वह समझाइश के बाद घर लौट आई थी। गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात मैंने उसे युवक से फोन पर बात करते हुए रंगे हाथों

पकड़ लिया था। इसी बात को लेकर पत्नी से कहासुनी हुई। तड़के 3:30 बजे मेरी नींद खुली। तब पत्नी का शव पास ही में फांसी के फंदे पर लटका देखा। शव को उतारने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए रवाना कर दिया। पोस्ट मार्टम के बाद बॉडी को परिजनों के हवाले कर दिया गया है।

पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त किया

घटना स्थल पर पहुंची पुलिस को शव के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उसके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस मोबाइल फोन का परीक्षण कराएगी। पति के डिटेल बयानों को दर्ज कर लिया गया है। मृतका के मायके पक्ष के डिटेल बयान फिलहाल दर्ज नहीं किए जा सके हैं।

हिंदी विरोध के जरिए राष्ट्रीय मानस पर चोट

इसे राजनीतिक विद्रूप ही कहेंगे कि हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार देने वाली मराठी माटी पर ही हिंदीभाषियों को अपमानित किया जा रहा है। महाराष्ट्र की धरती पर हिंदीभाषियों को अपमानित करने में राजनीति के दो चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ अपमानित करने वाली शिवसेना और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे है तो दूसरी तरफ राज्य की सत्ता है। हिंदीभाषियों को अपमानित करने वाली राजनीति का मकसद हिंदी विरोध पर मराठी मानुष की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए अपना वोट बैंक मजबूत करना है तो दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष के एक हिस्से की राजनीति है, जो अपमानित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इस डर से नहीं कर रही कि कहीं इससे मराठी मानुष की धारणा कमजोर ना हो जाए और उसके जरिए उसका अपना समर्थक आधार ना खिसक जाए। राजनीति की इस चक्रवर्तिनी में निम्न मध्यवर्गीय या हाशिये वाला हिंदीभाषी समुदाय ही पिस रहा है। उसका अपराध यह है कि वह महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी ना बोलकर हिंदी बोल रहा है।

हिंदी बोलने के लिए हिंदीभाषियों को प्रताड़ित करने वाली राजनीति का अतीत भी ऐसा ही रहा है। शिवसेना का उभार पिछली सदी के साठ के आखिरी वर्षों में मुंबई में मलयालम बोलने वालों को खिलाफ आंदोलन के बाद हुआ। मनसे के कार्यकर्ता 2008-09 के दौरान तो केंद्रीय नौकरियों के लिए मुंबई में परीक्षाएं देने आए उत्तर भारतीय विशेषकर उत्तर प्रदेश-बिहार के छात्रों को को खुलेआम पिटते रहे। उस समय की राज्य सरकार ने इस बदसलूकी के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने से बचती रही थी और आज की सरकार का भी कुछ वैसा ही रवैया है। मराठी मानुष का बोध महाराष्ट्र में इतना गहरा है कि सरकारें चाहें जिस भी दल की हो, इस मसले पर तकरीबन एक जैसा रुख अपनाने से परहेज नहीं करतीं। भारत की संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने का विचार देने में महाराष्ट्र की हस्तियों का बड़ा योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक ने बंग-भंग के वक्त 1905 में वाराणसी की यात्रा की थी। वहां उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जो कहा था, उसे महाराष्ट्र की हिंदीविरोधी राजनीति को जानना चाहिए। तिलक ने कहा था, 'निस्संदेह हिंदी ही देश की संपर्क



और राजभाषा हो सकती है। लोकमान्य अकेले मराठी मानुष नहीं हैं, जिन्होंने हिंदी को लेकर यह विचार दिया। 1960 से पहले आज का गुजरात राज्य भी महाराष्ट्र का ही हिस्सा था। 1880 में गुजराती कवि नर्मदाशंकर दवे उर्फ नर्मद कवि ने लोकमान्य से करीब चौथाई सदी पहले हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में आगे लाने का सुझाव दिया था। हिंदी को स्थापित करने की महात्मा गांधी की कोशिशों से भला कौन इनकार कर सकता है। 1918 में गांधी जी की अध्यक्षता में हुए इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन को हर हिंदीप्रेमी जानता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि गांधी जी ने 1917 में भरूच में आयोजित गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में पहली सार्वजनिक तौर पर हिंदी की ताकत को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था, भारतीय भाषाओं में केवल हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। हिंदी के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर भी मराठी भाषी ही थे। सतारा में जन्मे कालेलकर ने 1938 में कहा था, 'राष्ट्रभाषा प्रचार हमारा राष्ट्रीय कर्म है।' रचनात्मक आंदोलनकारी और गांधी जी के शिष्य विनोबा भी ताजिदंगी हिंदी के संघर्षरत रहे। उन्होंने हर भारतीय भाषा को एक-दूसरे के करीब लाने के लिए अनूठा सुझाव दिया था। उन्होंने हर भाषा से नागरी लिपि अपनाने का सुझाव दिया था। सिर्फ राजनीति ही नहीं, पत्रकारिता जगत की

मराठीभाषी हस्तियों ने भी हिंदी को स्थापित करने में रचनात्मक भूमिका निभाई है और साहस दिखाया है। हिंदी पत्रकारिता आज जिस मुकाम पर है, उसमें बड़ा योगदान मराठीभाषी पत्रकारों और लेखकों का भी है। माधव राव सप्रे, बाबूराव विष्णुराव पराडकर, रामकृष्ण खाडिलकर, लक्ष्मण नारायण गर्दे जैसे पत्रकारों ने हिंदी को नई शैली में गढ़ा, उसके शब्द गढ़े, और उसे ऊंचाई दी। हिंदी इन मराठीभाषी महात्मनों की शुरुगुजार है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से निकले धर्मयुग ने दशकों तक हिंदीभाषी पाठकों के दिलों पर राज किया। ऐसे महाराष्ट्र की धरती पर अगर हिंदी बोलने वालों का अपमान होना दुखद ही कहा जाएगा। हिंदी को लेकर महाराष्ट्र की धरती पर अतीत में ऐसी सोच नहीं रही है। हिंदी विरोध की ग्रंथि तमिलनाडु में आजादी के पहले से ही रही है, जिसका संक्रमण कर्नाटक तक पहुंचा है। कर्नाटक रक्षण वेदिके ने 2017 में हिंदी बेड़ा अभियान यानी हिंदी विरोधी अभियान चलाया। साल 2019 में हिंदी दिवस न मनाने के लिए भी राज्य में अभियान चला। शुरू में इन विरोध प्रदर्शनों को बड़ा समर्थन नहीं मिला। राजनीति और मीडिया के हलकों में इसकी सुरसुरी दिखी। ऐसे आंदोलनों का असर बाद में पता चलता है। जब विरोध की वैचारिकी के असर में जमीनी स्तर की सोच बदलने लगती है। एक राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थानीय शाखा के प्रबंधक से जबरदस्ती

हिंदी बोलने के लिए हुज्जत करने का दृश्य हो या फिर किसी ऑटोवाले का किसी हिंदीभाषी लड़की को थप्पड़ मारना, कर्नाटक में हिंदी विरोधी आंदोलन की जमीनी परिणति ही कहा जाएगा। निजाम का शासन कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में रहा। दिल्ली सल्तनत के बादशाह मोहम्मद तुगलक ने 1327 ईस्वी में दिल्ली से महाराष्ट्र के दौलताबाद में अपनी राजधानी लेकर गया था। जिसे आज का महाराष्ट्र देवगिरि के नाम से जानता है। उसके साथ भी हिंदी वहां तक पहुंची थी। महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका राज्य पुनर्गठन से पहले मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा रहा। इस वजह से विदर्भ भी मोटे तौर पर हिंदी के प्रभाव वाला राज्य है। शायद यही वजह रहा कि महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विवाद नहीं रहा। विवाद की वजह अब मनसे और शिवसेना की राजनीति बनी है। इसका कारण नई शिक्षा नीति का वह प्रावधान है, जिसके तहत प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं के जरिए शिक्षा देने का प्रावधान है। इसके तहत जब प्राथमिक स्तर पर हिंदी में पढ़ाई कराने का आदेश आया तो राज्य की राजनीति में अपनी जगह खोज रहे शिवसेना-उद्धव और मनसे को हिंदी विरोध में ही अपना भविष्य नजर आया। एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद से शिवसेना-उद्धव भी परेशान है और शिवसेना से अलग होने के बाद से मनसे प्रमुख राज ठाकरे अपना राजनीतिक वजूद की खोज में हैं। दिलचस्प यह भी है कि अतीत में सत्ता और उत्तराधिकार के चलते अलग राह चुनने वाले दोनों चचेरे भाई उद्धव और राज एक कश्ती पर सवार होने की तैयारी में हैं और उसके लिए उन्होंने हिंदी विरोध की नाव तैयार की है। हिंदी विरोध को लेकर सवाल यह भी है कि मराठी मर्द राज ठाकरे की ताकत हजारों करोड़ का कारोबार करने वाली हिंदी फिल्मों के गढ़ में जाने से क्यों हिचकती है? कर्नाटक हो या तमिलनाडु, वहां के भी फिल्म निर्माताओं को जब सौ, दो सौ या पांच सौ करोड़ क्लब में शामिल होना होता है, हिंदी के बाजार पर ही उनका ध्यान जाता है। हिंदी के बाजार से प्यार और हिंदीभाषियों से दुर्व्यवहार-दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जिस तरह का व्यवहार हिंदीभाषियों के साथ हिंदी विरोध के नाम पर हो रहा है, अगर वैसा ही व्यवहार इन राज्यों के निवासियों के साथ हिंदीभाषी इलाकों में होने लगे तो क्या होगा।

17 देशों की संसदों में संबोधन, 27 देशों से सर्वोच्च सम्मान

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व के क्षेत्र में भारत को एक नई ऊँचाई पर पहुंचा दिया है। जहां एक ओर उन्होंने अब तक 17 देशों की संसदों को संबोधित कर भारत की आवाज को विश्वमंच पर मुखर किया है, वहीं दूसरी ओर 27 देशों से प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मानों ने उन्हें दुनिया के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली नेताओं में स्थान दिला दिया है। यह उपलब्धियाँ केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति की उन्नति का प्रतिबिंब हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संसदों में संबोधन केवल भाषण नहीं, बल्कि रणनीतिक कूटनीति का हिस्सा है। उन्होंने विकसित और विकासशील देशों, दोनों के विधायी मंचों पर भारत की लोकतांत्रिक विरासत, आर्थिक दृष्टि और वैश्विक सहयोग की भावना को साझा किया। मोदी की ओर से अन्य देशों की संसदों में दिये गये संबोधन को याद करें तो उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिजी, भूटान, नेपाल की संसदों को संबोधित किया। साल 2015 में प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन, श्रीलंका, मंगोलिया, अफगानिस्तान और मॉरीशस की संसद को संबोधित किया। साल 2016 में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। 2018 में प्रधानमंत्री ने युगांडा और 2019 में मालदीव की संसद में अपना संबोधन दिया। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस में अपना संबोधन दिया और इसके साथ ही वह उन कुछ चुनिंदा वैश्विक हस्तियों में शुमार हो गये जिन्हें दो बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने का गौरव हासिल हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 2024 में गुयाना और 2025 में घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा नामीबिया की संसद को संबोधित किया। खास बात यह है कि 2025 में तीन देशों की संसदों में प्रधानमंत्री का संबोधन एक सप्ताह के भीतर हुआ है जोकि अपने आप में एक और कीर्तिमान है। इन सभी संबोधनों में भारत ने ग्लोबल साउथ, संयुक्त राष्ट्र सुधार, आतंकवाद विरोध, जलवायु न्याय और डिजिटल समावेशन जैसे मुद्दों पर स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 देशों की संसदों को संबोधित करना और 27 देशों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करना, भारतीय विदेश नीति के इतिहास में एक अभूतपूर्व अध्याय है। यह दर्शाता है कि आज का भारत केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा देने वाला देश बन चुका है। यह उपलब्धि भारतवासियों के आत्मविश्वास, आकांक्षाओं और अंतरराष्ट्रीय भूमिका को सशक्त करती है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व दौरों की चर्चा प्रायः उनकी रणनीतिक कूटनीति, वैश्विक नेतृत्व और द्विपक्षीय समझौतों के संदर्भ में होती है, किंतु इन यात्राओं में एक और विशेष पक्ष होता है जो चुपचाप भारत की आत्मा को विश्व के सामने प्रस्तुत करता है— वह है उनके द्वारा चयनित सांस्कृतिक उपहार। हम आपको बता दें कि हर दौरे में प्रधानमंत्री मोदी जिन विशिष्ट हस्तशिल्पों, कलाकृतियों और प्रतीकों को उपहार स्वरूप ले जाते हैं, वे केवल शिष्टाचार नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध परंपरा, बहुसंस्कृतिक और आत्मनिर्भर कलात्मकता का परिचायक होते हैं। यह सांस्कृतिक कूटनीति भारत की सॉफ्ट पावर को सशक्त करने में निर्णायक भूमिका निभा रही है।

मानसून सत्र से ई विधान सिस्टम लागू नहीं हो सकेगा

विधायकों के लिए टैबलेट नहीं खरीद पाया एनआईसी; शीतकालीन सत्र तक टलेगी नई व्यवस्था



न्यूज क्राइम फाइल

विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों को टैबलेट नहीं मिल पाएंगे। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की इसको लेकर प्रोसेस पूरी नहीं हो पाने के चलते एक साल पहले मानसून सत्र से

विधानसभा की कार्यवाही में ई विधान लागू करने का फैसला भी अटक सकता है। अब तक की स्थिति में यह मानसून सत्र में लागू नहीं होगा और शीतकालीन सत्र के लिए इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के विधायकों को ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन सवाल

करने की आदत डालने के बाद अब विधानसभा सचिवालय उन्हें टैबलेट के जरिए सूचनाओं के आदान-प्रदान में पारंगत करना चाहता है। केंद्र सरकार की मंशा के मुताबिक विधानसभा में ई विधान लागू करने का फैसला पिछले साल लिया गया था और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इसी मानसून सत्र से शुरू करने का निर्णय लिया था। एनआईसी ने भी तब सहमति दी थी।

इसके बाद यहां बैठकों का दौर चलता रहा लेकिन अब जबकि मानसून सत्र शुरू होने को 18 दिन का समय बाकी है तो यह बात सामने आई है कि विधायकों को टैबलेट देने के लिए एनआईसी टेंडर प्रोसेस ही पूरी नहीं कर पाया है। इसलिए इस सत्र से यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकेगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है कि विधानसभा सचिवालय की तैयारियां पूरी हैं। केवल लगाने का काम हो चुका है लेकिन यह जानकारी मिली है कि टैबलेट आने की प्रोसेस एनआईसी पूरी नहीं कर सका है। इसलिए इस बार यह व्यवस्था शुरू होना संभावित नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश में विधायकों के लिए 250 अत्याधुनिक टैबलेट की खरीदी किया जाना है और इसका उपयोग मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी विधायक कर सकेंगे। टैबलेट का उपयोग सदन की कार्यवाही के दौरान और सदन के बाहर किया जा सकेगा।

उज्जैन में पैसों के विवाद में दोस्त की हत्या

कालिदास उद्यान में सिर कुचला, पुलिस ने 5 घंटे में दो आरोपियों को पकड़ा



न्यूज क्राइम फाइल

उज्जैन के कालिदास उद्यान में एक कबाड़ी व्यवसायी की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान मदीना कॉलोनी निवासी राजा सिमरैया (45) के रूप में हुई है। पुलिस ने पांच घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 9 जुलाई की शाम की है। राजा अपने दोस्त अमन और अजीमुद्दीन के साथ कालिदास उद्यान गया था। वहां अमन ने राजा से पैसे उधार मांगे। राजा के मना करने पर विवाद हो गया। अमन और अजीमुद्दीन ने पहले राजा के सिर पर गमला मारा। फिर एक बड़े पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया। राजा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। मुखबिरों से जानकारी जुटाई। साक्ष्य एकत्र किए। इसके बाद जूना सोमवारिया निवासी अमन (25) और जानसापुरा निवासी अजीमुद्दीन (19) को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा। एसपी प्रदीप कुमार शर्मा के निर्देश पर एसपी नीतेश भार्गव और सीएसपी राहुल देशमुख के मार्गदर्शन में विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। टीम में थाना प्रभारी गगन बादल समेत क्राइम ब्रांच के अधिकारी शामिल थे।

पत्रकार बनने का सुनहरा अवसर

अगर आपके अंदर लिखने का कौशल है और पत्रकारिता में रुचि है, तो 'न्यूज क्राइम फाइल' को आपकी तलाश है। 'न्यूज क्राइम फाइल' से जुड़ कर आप हर माह दस हजार रुपये तक कमा सकते हैं। 'न्यूज क्राइम फाइल' भोपाल, ग्वालियर, सतना, सागर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और नीमच में ब्यूरो ऑफिस खोलने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार तत्काल हमें अपना बायोडाटा मेल करें या व्हाट्सअप करें।

उदय प्रताप सिंह चौहान (संपादक) 07223003441

website: www.newscrimfile.com

email: newscrimfile@yahoo.com



सीएम ने विभागों में रिक्त पदों की समीक्षा की एसीएस को निर्देश; भर्ती और पदोन्नति की नियमित समीक्षा हो, विभागों से रिपोर्ट मंगाएं

न्यूज क्राइम फाइल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जिन विभागों में पद रिक्त हैं, उन्हें जल्दी से भरने की कार्रवाई की जाए। रिक्त पदों पर लगातार नियुक्ति होने से विभागों के नियमित कार्यों में गति आ रही है और इसमें और भी सुधार की स्थिति बनेगी। उन्होंने कहा कि सालों बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू किए जाने से बड़ी संख्या में उच्च पदों पर नियुक्ति का कार्य आसान हो रहा है। सीनियर अधिकारी शासकीय भर्तियों के कार्य की लगातार समीक्षा कर रिपोर्ट दें।

सीएम बोले- विभागों में नियुक्तियों की लगातार समीक्षा भी की जाए

गुरुवार को समत्व भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों और सरकार द्वारा की जा रही भर्ती की समीक्षा की। मुख्य सचिव अनुराग जैन, जीएडी के नए एसीएस संजय कुमार शुक्ल, सीएम के एसीएस नीरज मंडलोई की मौजूदगी में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉ.



यादव ने कहा कि विभागों में नियुक्तियों की लगातार समीक्षा भी की जाए। मुख्य सचिव स्तर और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों को समय सीमा में कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। विभागों से यह भी जानकारी ली जाए कि कितने पदों पर भर्ती हो चुकी है और कितने

पदों के लिए बाकी है। इस कार्य को आवश्यक समन्वय और सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग संजय कुमार शुक्ल ने लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल और अन्य स्तर से नए शासकीय भर्तियों की प्रगति से अवगत कराया।

5 करोड़ की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया

न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल के अनंतपुर में गुरुवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया की मौजूदगी में अमले ने सरकारी जमीन पर खड़े पक्के निर्माण को जमींदोज कर दिया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी ने कब्जा हटाने के आदेश दिए थे। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। ताकि, हंगामा होने पर सख्ती से निपटा जा सके। पुलिस ने सड़क के दोनों ओर से बेरिकेडिंग भी की थी। इस मामले में तहसीलदार त्रिपाठी ने नोटिस भी जारी किया था। बावजूद निर्माण नहीं तोड़ा गया। सोहेल अहमद निवासी अनंतपुर का जमीन पर कब्जा था। 3 हजार स्क्वायर फीट जमीन पर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का व्यवसायिक निर्माण कर कब्जा किया था।

सौजन्य भेंट



उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सनातन धर्म के ध्वजवाहक, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर एवं श्री बालाजी महाराज के अनन्य उपासक परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को जन्मदिवस की शुभकामनाएँ दी।

भोपाल में बिना परमिट-फिटनेस चल रही स्कूल वैनें जब्त



न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल में गुरुवार को चुना भट्टी और कोलार रोड इलाके में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सात स्कूल वैन और मैजिक वाहन जब्त किए गए। ये सभी वाहन बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और बीमा के स्कूल बच्चों को लेकर सड़कों पर दौड़ रहे थे। जब्त किए गए वाहनों में सेंट मैरी स्कूल और मदर टेरेसा स्कूल के छात्र-छात्राएं सवार थे। कार्रवाई के दौरान सभी वाहनों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और यातायात थाना परिसर में निराकरण हेतु खड़ा किया गया है। परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने इस कार्रवाई को बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर कदम बताया। बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहनों के लिए फिटनेस, बीमा और वैध परमिट अनिवार्य हैं। इनका उल्लंघन करना सीधे तौर पर बच्चों की जान जोखिम में डालने जैसा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में ऐसे वाहनों पर और भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।



गुरुग्राम में इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी की पिता ने की हत्या

खेल एकेडमी चलाने से नाराज था, बोला- लोग ताने मारते थे

न्यूज क्राइम फाइल

हरियाणा के गुरुग्राम में 25 साल की जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजन के मुताबिक पिता ने टेनिस एकेडमी खोलने के लिए सवा करोड़ रुपए दिए थे। एक महीने बाद ही उन्होंने एकेडमी बंद करने के लिए बेटी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। घटना गुरुवार की है। परिजन के मुताबिक 15 दिन से घर में क्लेश था। बाप-बेटी में रोजाना झगड़ा हो रहा था। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थीं, जिससे अच्छी कमाई हो रही थी। उसके पिता दीपक यादव को लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। आरोपी पिता ने उसे टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा। लेकिन, राधिका नहीं मानी और दोनों के बीच बहस हो गई। जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर उसे गोलियां मार दीं। हालांकि, पहले सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर हत्या करने की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित सुशांत लोक फेस-2 में सामने आया।

1. किचन में खाना बनाते वक्त 3 गोलियां मारीं

आरोपी दीपक के भाई कुलदीप यादव ने पुलिस से शिकायत की है। कुलदीप ने बताया कि गुरुवार सुबह दीपक का अपनी बेटी राधिका के साथ एकेडमी बंद करने को लेकर विवाद हुआ था। जब राधिका किचन में खाना बना रही थी, उसी वक्त दीपक ने पीछे से उसे अपनी लाइसेंस पिस्टल से 3 गोलियां मार दीं।

2. रसोई में खून से लथपथ पड़ी थी राधिका

कुलदीप ने कहा कि सुबह के समय मैं ग्राउंड फ्लोर पर था। मैंने तेज आवाज सुनी और जब मैं पहली मंजिल पर गया तो राधिका को रसोई में खून से लथपथ पड़े पाया। जबकि पिस्टल ड्राइंग रूम में पड़ी थी। मैं और मेरा बेटा उसे एशिया मैरिंगो अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

3. मर्डर के बाद वहीं बैठा रहा पिता

कुलदीप ने कहा कि मेरे भाई ने पॉइंट थ्री टू बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया और वह उसी की थी, जिसका लाइसेंस भी है। राधिका किचन में खून से लथपथ पड़ी थी और दीपक भी पास में बैठा था। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने दीपक को हिरासत में ले



लिया। बेटी राधिका यादव बड़ी खिलाड़ी थीं- सेक्टर थाना 57 के प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी दीपक बिल्डर है। फ्लैट बनाकर किराए पर देता है। पूछताछ में दीपक ने कहा कि राधिका बड़ी खिलाड़ी थी। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई पदक जीत चुकी थी। इस बात पर पूरे परिवार को गर्व था। मैं भी बेटी राधिका पर गर्व करता था।

कंधे में चोट लगी तो टेनिस एकेडमी खोल ली: दीपक ने कहा कि करीब 3 माह पहले राधिका के कंधे में चोट लग गई थी। यह चोट टेनिस खेलते वक्त ही लगी थी। उन्होंने डॉक्टर से इलाज कराया। चोट से तो आराम मिल गया, लेकिन बेटी ने टेनिस खेलना छोड़ दिया। इसके बाद राधिका ने अपनी एकेडमी खोल ली, जहां वह लड़के-लड़कियों को टेनिस सिखाती थीं।

लोग मारते थे ताना, बेटी की कमाई खा रहा है: दीपक ने आगे कहा कि जब मैं दूध लेने जाता था तो लोग ताना मारते थे। कहते थे तेरी बेटी तो बढ़िया पैसा कमा रही है। तेरे मजे हैं, तू बेटी की कमाई खा रहा है। मजे हैं तेरे और तेरे परिवार के। लोगों की यह बात मुझे चुभती थी। मैंने कई बार इस बारे में राधिका से भी बात की थी।

टेस्ला का भारत में पहला शोरूम 15 जुलाई को खुलेगा

पांच मॉडल गाड़ियां पहले ही मुंबई पहुंच चुकी, कीमत 48 लाख

न्यूज क्राइम फाइल

इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला 15 जुलाई को भारत में अपना पहला स्टोर शुरू करने वाली है। ये स्टोर मुंबई में खुल रहा है और लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर काम करेगा। यानी यहां न सिर्फ गाड़ियां बेची जाएंगी, बल्कि लोग टेस्ला की टेक्नोलॉजी और फीचर्स को भी करीब से देख सकेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ये जानकारी दी है। कंपनी ने बीते दिनों मुंबई के ब्रांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 4,000 वर्ग फीट के रिटेल स्पेस के लिए लीज साइन की थी। यह जगह शहर में स्थित एपल के फ्लैगशिप स्टोर के करीब है। पहले चरण में टेस्ला अपने मॉडल 3 इलेक्ट्रिक को ला रही है, जो शंघाई फैक्ट्री से इंपोर्ट की गई है। भारत में इसकी कीमत करीब 48 लाख रुपए हो सकती है।

48 लाख रुपए की कार पर 21 लाख की इंपोर्ट ड्यूटी



ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के शंघाई फैक्ट्री से पांच मॉडल वाय गाड़ियां पहले ही मुंबई में टेस्ला के शोरूम में पहुंच चुकी हैं। टेस्ला की इन गाड़ियों की कीमत 27.7 लाख है और इन पर 21 लाख से ज्यादा का इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। यानी, कीमत करीब 48 लाख हो जाएगी। ये ड्यूटी भारत के उस 70वें टैरिफ के हिसाब से है, जो 40,000 से कम कीमत वाली आयातित गाड़ियों पर लगता है।

इसमें अतिरिक्त शुल्क भी शामिल हैं।

इंडिया हेड का इस्तीफा, चीनी टीम ऑपरेशंस संभाल रही

हाल के दिनों में भारत में अपनी लीडरशिप में बदलाव के बावजूद, टेस्ला अपने प्लान्ड रोलआउट के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। कंपनी के इंडिया हेड, प्रशांत मेनन ने पिछले महीने नौ साल की सर्विस के बाद इस्तीफा दे दिया था। ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक, फिलहाल

टेस्ला की चीन स्थित टीम भारत के ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है, और अभी तक कोई नया उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है।

मॉडल वाय दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार

कंपनी की मॉडल वाय दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। ये भारतीय ग्राहकों को भी पसंद आ सकती है। कंपनी ने अमेरिका, चीन और नीदरलैंड से सुपरचार्जर कंपोनेंट, कार एक्सेसरीज, मर्चेन्डाइज और स्पेयर्स भी इंपोर्ट किए हैं। टेस्ला का भारत में आना इसलिए भी खास है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। कंपनी को यूरोप और चीन में बिक्री में कमी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में भारत उनके लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेस्ला ने मुंबई के BKC में मेकर मैक्सिटी बिल्डिंग में 5 साल के लिए जगह किराए पर ली है।



एसपी ने आरोपी पर किया 5 हजार का इनाम घोषित, पीड़िता ने लगाए पुलिस पर बचाने के आरोप

जबलपुर देह व्यापार कांड में मुख्य सरगना फरार



न्यूज क्राइम फाइल

जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र में करीब एक माह पहले सामने आए देह व्यापार के मुख्य आरोपी शीतल दुबे उर्फ मथुरा प्रसाद को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है। एसपी संपत उपाध्याय ने बुधवार

को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी को पुलिस जानबूझकर बचा रही है। इस मामले में भाजपा के मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्हें पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया है। गढ़ा क्षेत्र में देह व्यापार चलने की शिकायत असम की एक महिला ने की थी। इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अतुल चौरसिया को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी फरार हो गया था। अब महिला ने आरोप लगाए हैं कि डिंडोरी के गल्ला गोदाम क्षेत्र निवासी मुख्य आरोपी को पुलिस बचा रही है। बता दें कि 1 जून को गढ़ा पुलिस ने होटल अतिथि में छपा मारकर देह व्यापार के अड्डे का खुलासा किया था।

शीतल ने दिलाई थी पीड़िता को होटल में नौकरी

पीड़िता ने बताया था कि वह वर्ष 2023 में जबलपुर आई थी और एक पार्लर में काम करने के दौरान उसकी पहचान शीतल दुबे से हुई थी। बाद में शीतल ने उसकी मुलाकात अतुल चौरसिया से कराई और होटल में नौकरी दिलवाई।

पुरुषों के साथ जबरिया भेजा जाता था

महिला ने आरोप लगाया कि होटल में उसे अन्य युवतियों के साथ रखा जाता था और पुरुषों को उनके साथ जबरन भेजा जाता था। इनकार करने पर उसे धमकाया गया और बंधक बनाकर शारीरिक शोषण किया गया। नवंबर 2024 में अतुल चौरसिया ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया था। पुलिस ने छापे के दौरान अतुल चौरसिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन शीतल दुबे अब तक फरार है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस की धीमी कार्रवाई से उसे न्याय मिलने में विलंब हो रहा है।

हर ग्राहक से 2 से 5 हजार रुपए तक वसूलते थे

पीड़िता ने बताया कि होटल में आने वाले पुरुषों को सीधे उसके कमरे में भेजा जाता था। हर ग्राहक से 2 से 5 हजार रुपए लिए जाते थे, लेकिन उसे उसमें से बहुत कम पैसा दिया जाता। जब भी वह पैसे मांगती, तो बहला-फुसलाकर चुप करा दिया जाता। कई बार पैसे मांगने पर उसे धमकाया भी गया।

गुना में सांड ने महिला को उठाकर पटका

पानी का बर्तन सर पर रखकर जा रही थी, घायल; लोग बोले- शहरभर में घूम रहे आवारा मवेशी

न्यूज क्राइम फाइल

गुना जिले में आवारा मवेशियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बूढ़े बालाजी इलाके में सर पर पानी का बर्तन लेकर घर जा रही वृद्ध महिला को सांड ने उठाकर पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना 7 जुलाई की है, जिसका सीसीटीवी आज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक घर के बाहर दो सांड खड़े हैं। जब महिला पानी का बर्तन लेकर अपने घर में प्रवेश करने जा रही थीं, तभी एक सांड ने उन्हें सींगों से उठाकर पटक दिया। हादसे में महिला घायल हो गई थी, जिन्हें स्थानीय लोगों ने तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनका इलाज किया गया।



नेशनल हाईवे पर बैठा रहता है झुंड स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के

मौसम में आवारा मवेशियों की समस्या और भी विकराल हो गई है। नेशनल हाईवे पर मवेशियों

के झुंड बैठे रहते हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे सड़क हादसे का डर भी बना रहता है। शहर की मुख्य सड़कों और गलियों में घूमते आवारा सांड आए दिन लोगों को घायल कर रहे हैं।

नपा टीम बोली- पकड़ने पर गोरक्षक आपत्ति जताते हैं

बता दें कि, वर्ष 2022 में तत्कालीन सांसद केपी यादव ने नगरपालिका को दी गई सांड पकड़ने वाली ट्रॉली का उपयोग शुरुआती दिनों के बाद से बंद कर दिया गया है। नगरपालिका का कहना है कि जब उनकी टीम सांड पकड़ने जाती है, तो कुछ गोरक्षक आपत्ति जताते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। इस कारण यह ट्रॉली अब धूल फांक रही है और समस्या जस की तस बनी हुई है।



सुसाइड नोट में प्रेमिका पर लगाए आरोप; 10 लोगों से 10.68 लाख लेने की बात लिखी

विदिशा मेडिकल कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर ने लगाई फांसी

न्यूज क्राइम फाइल

विदिशा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर ने गुरुवार सुबह अपने क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कॉलेज की कर्मचारी कॉलोनी स्थित 14 नंबर बिल्डिंग में रहता था। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट और कई दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान भोपाल निवासी दीपक ठकोरिया (38) पिता नंदराम ठकोरिया के रूप में हुई है। वो 2018 से मेडिकल कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। दीपक ने घर में पंखे से रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने प्रेमिका और उसके परिवार पर आर्थिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। वहीं 12 लोगों को दी गई कुल 10.68 लाख रुपए की उधारी का विवरण भी लिखा है।

प्रेमिका सोनाली पर लगाए आरोप, कार्रवाई की मांग की

दीपक ने नोट में रायसेन की सांचेत निवासी प्रेमिका सोनाली नामदेव पर झूठे प्यार का नाटक कर उससे राशन, कपड़े और गहने लेने का आरोप लगाया है। साथ ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से लाखों रुपए हड़प लिए। युवक ने प्रेमिका सोनाली नामदेव के पिता और भाई पर भी पैसे लेने का आरोप लगाया है।

एक फाइल में सुसाइड नोट सहित सबूत छोड़े

दीपक ने आगे लिखा कि वो लंबे समय से मानसिक और आर्थिक परेशानी झेल रहा है। उसने एक फाइल में सभी ट्रांजैक्शन की कॉपी और सुसाइड नोट रखा था। साथ ही प्रेमिका के



दीपक ठकोरिया, मृतक

खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीएसपी अतुल सिंह मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

माता-पिता और भाई की हो चुकी मौत

परिजनों के अनुसार, दीपक के पिता की मौत कैंसर से हुई थी। मां का पहले ही देहांत हो चुका था और छोटा भाई की भी करंट लगने से मौत हो गई थी। दीपक की तीन बहनें हैं। बड़ी बहन सुनीता, दूसरे नंबर की सीमा और तीसरे नंबर की बहन रजनी, सभी की शादी हो चुकी है। सीमा और रजनी घटना की जानकारी मिलते ही विदिशा मेडिकल कॉलेज पहुंची और उनके दो चाचा अशोक और कालीचरण ठकोरिया भी मौके पर पहुंच गए हैं।

अनुकंपा के तहत मिली थी सहायक ग्रेड-3 की नौकरी

पिता की मौत के बाद साल 2018 में दीपक को हमीदिया अस्पताल में अनुकंपा नियुक्ति के



सोनाली नामदेव, आरोपी

तहत मेडिकल कॉलेज, विदिशा में सहायक ग्रेड-3 की नौकरी मिली। वर्तमान में वो स्थापना शाखा में पदस्थ था और अकेले रहता था।

सगाई की बात बताई, लड़की से कभी नहीं मिलवाया

बताया गया कि दीपक धार्मिक प्रवृत्ति का था, वो शाकाहारी और पूजा-पाठ करने वाला व्यक्ति था। मांस-मदिरा से दूर रहता था और ऑफिस में सभी से हंसकर बात करता था। करीब एक साल पहले उसने अपनी सगाई की बात सबको बताई थी, लेकिन कभी भी उस लड़की से किसी को नहीं मिलवाया। दीपक ने कई बार उस लड़की का मेडिकल कॉलेज में इलाज भी करवाया था।

4 बार आत्महत्या की कोशिश, हर बार लिखा सुसाइड नोट

रिश्तेदार ने बताया कि दीपक ने चार बार

नोट में लिखा उधारी का विवरण-

पल्लवी श्रीवास्तव (नर्सिंग इंचार्ज, विदिशा मेडिकल कॉलेज): 2,50,000
प्यारी चौटाला (गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल): 2,40,000
निशा पाटील (विदिशा मेडिकल कॉलेज): 2,14,000
सतीश चौटाला (शहीद नगर, भोपाल): 70,000
मोहन पगारे (शहीद नगर, भोपाल): 70,000
मुकेश कटारे (कबीरपुरा): 70,000
नेहा चौधरी (लालघाटी, भोपाल): 60,000
टिंकू भैया (आनंद नगर, भोपाल): 40,000
सीमा (शहीद नगर, भोपाल): 38,000
राजू (गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल): 16,000

आत्महत्या करने की कोशिश की थी और हर बार उसने एक सुसाइड नोट लिखा। वही सुसाइड नोट एक साथ फाइल में लगाए गए हैं।

10 लोगों पर 10.68 लाख थे बकाया

कर्मचारी दीपक की आत्महत्या के मामले में सुसाइड नोट से बड़ा खुलासा हुआ। दीपक ने नोट में 12 लोगों को दी गई कुल 10.68 लाख रुपए की उधारी का विवरण दिया है। दीपक ने लिखा है कि वह इन लोगों से बार-बार पैसे मांगते-मांगते थक गया था। उसने स्पष्ट किया है कि उसकी मौत के लिए इन लोगों को दोषी न माना जाए, लेकिन उधार की राशि उसकी बहन को लौटाई जाए।

टाइगर से भिड़ा युवक, सिर-हाथ में गहरे घाव: बालाघाट में डंडे से मारकर भगाया; घायल हालत में 200 मीटर चलकर खुद बेटे को बुलाया

न्यूज क्राइम फाइल

बालाघाट में एक युवक पर बाघ ने पीछे से हमला कर दिया। उसके सिर और हाथ में गहरी चोट आई है। जान बचाने के लिए वह बाघ से भिड़ गया। उसपर डंडे बरसाए। इसके बाद बाघ वहां से भाग गया। घटना बुधवार को कंटंगी वन परिक्षेत्र के कन्हड़ागांव बीट में हुई। हमले में घायल युवक 200 मीटर पैदल चला। इसके बाद फोन पर बेटे को सूचना दी। बेटे ने वनविभाग को जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम ने घायल को कंटंगी अस्पताल भेजा। यहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। युवक का नाम बस्तीराम है। वह जंगल में जानवरों को चराने गया था। परिक्षेत्र सहायक बाबूलाल चट्टार ने बताया कि बस्तीराम की हालत स्थिर है। वन विभाग ने तत्काल सहायता के रूप में 5 हजार रुपए दिए हैं। इलाज का पूरा खर्च भी विभाग वहन करेगा।

लोगों को जंगल नहीं जाने की सलाह

बालाघाट के कंटंगी सामान्य परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चट्टार ने बताया है कि लोगों को जंगल में न जाने की सलाह दी गई है। जिस स्थान पर बाघ ने हमला किया है वहां पर उसकी मूवमेंट होने के कारण विभाग ने लोगों को न जाने की सलाह दी गई।





एक घंटे में 14 किलो ड्राई फूट्स खा गए अफसर

शहडोल में 5 दिन में दूसरा बड़ा घोटाला; 6 लीटर दूध में 5 किलो शक्कर डालकर बनी चाय

न्यूज क्राइम फाइल

मध्यप्रदेश के शहडोल में स्कूल में ऑयल पेंट घोटाले के बाद सरकारी धन के दुरुपयोग करने का दूसरा मामला सामने आया है। जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम में अफसर एक घंटे के दौरान 14 किलो ड्राईफूट खा गए। वहीं 6 लीटर दूध में 5 किलो शक्कर डालकर चाय भी बनाई गई। कार्यक्रम 25 मई को भदवाही ग्राम पंचायत में हुआ था। इसमें कलेक्टर डॉ. केदार सिंह, जिला पंचायत सीईओ नरेंद्र सिंह, जयसिंह नगर की एसडीएम प्रगति वर्मा और जनपद सीईओ समेत कई अधिकारी शामिल हुए थे। ग्राम पंचायत ने मेजबानी करते हुए अफसरों के लिए टेंट, भोजन और नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में लगाए गए बिल गुरुवार को सोशल मीडिया में वायरल हुए। इसके बाद ये मामला सामने आ सका। जिला पंचायत के प्रभारी सीईओ एमपी सिंह ने कहा कि हम लोग उस आयोजन में गए थे, लेकिन वहां इतना ड्राईफूट नहीं था। बिलों की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बोरी बंधान कार्यक्रम में पहुंचे थे कलेक्टर

भदवाही ग्राम पंचायत में झूझा नाला है। यह मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को तय करती है। इसी नाले में 25 मई 2025 को जिला स्तरीय बोरी बंधान कार्यक्रम का आयोजन रखा था। कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों ने बोरी में रेत भरकर नाले में पानी को रोकने का कार्य

क्र.	वस्तु का विवरण	मात्रा	दर	रकम
1	पूरी सब्जी	50	60	3000.00
2	मीठा	1kg	400	400.00
3	नमकीन	2kg	200	400.00
4	समोसे -	50	70	3500.00
5	पानी -	50	100	5000.00

किया। इस दौरान अफसर एक घंटे भदवाही में रहे। अधिकारियों ने फर्जी बिल के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया। ग्राम पंचायत से इस खर्च का भुगतान करवाया गया।

क्या है जल संवर्धन अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आह्वान पर जिले में भी गांव-गांव में जल गंगा संवर्धन अभियान समाज एवं सरकार के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से जहां पुरानी जल संरचनाओं कुआ, तालाब,

बावड़ियों, जल स्रोतों, गांव में बहने वाली नदियों एवं नालों की साफ-सफाई का कार्य किया गया है।

13 किलो ड्राईफूट के बिल का भुगतान

अफसरों के स्वागत सरकार में ग्राम पंचायत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 किलो काजू, 6 किलो बादाम और 3 किलो किशमिश खिलाने के नाम पर 19010 रुपए का भुगतान करवा लिया। अफसरों को चाय पिलाने के लिए 6

लीटर दूध और उसमें मिलाने के लिए 5 किलो शक्कर भी खरीदी गई। उसी बिल में 30 किलो नमकीन, 20 पैकेट बिस्कुट, 5 किलो शक्कर और 6 किलो दूध पर 19 हजार 10 रुपए व्यय किए गए।

एक किलो काजू के दो अलग-अलग रेट

25 मई 2025 को ग्राम पंचायत द्वारा एक और बिल लगाया गया। इसमें काजू के दाम में गिरावट देखी गई। दरअसल, जिस बिल में गोविंद गुप्ता किराना स्टोर ग्राम भरी से 5 किलो काजू लाया गया, उसमें काजू की कीमत प्रति किलो 1000 रुपए दर्शाई गई। इसी तारीख को सुरेश तिवारी टी स्टॉल चुहरी से एक किलो काजू मात्र 600 रुपए में खरीद लिया गया। इसके अलावा 10 रुपए वाले 50 रसगुल्ले भी अफसरों के लिए खरीदे गए। इसे 500 की जगह बिल में 1000 रुपए जोड़कर दाम बढ़ाया गया है।

ग्रामीणों को ड्राईफूट की जगह मिली खिचड़ी

ग्राम पंचायत ने अफसरों और ग्रामीणों को खिलाने के लिए पूरी और सब्जी की भी व्यवस्था की थी। पंचायत सरपंच और सचिव ने इसके लिए सुरेश तिवारी टी स्टॉल चुहरी और नारायण टी स्टॉल चुहरी से पूरी सब्जी के पैकेट खरीदे। साथ ही गोविंद किराना स्टोर से उसे बनाने वाला सामान भी खरीद लिया। भदवाही में जल चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें खिचड़ी, पूड़ी सहित सब्जी बनी थी, लेकिन काजू-बादाम सहित अन्य सामग्री नजर नहीं आई।

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म: शादी समारोह में हुई दोस्ती, 2 साल तक लिव-इन में रहे; केस दर्ज होते ही आरोपी फरार

न्यूज क्राइम फाइल

ग्वालियर में 21 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। प्रेमी शान खां युवती के साथ पिछले 2 साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रहकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। युवती जब भी शादी का कहती वह जल्द ही करने की बात कहकर टाल देता था। जब युवती ने प्रेमी पर दबाव बनाया तो वह शादी करने से साफ मुकर गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। धमकी, शोषण और धोखे की शिकार पीड़िता ने गुरुवार को थाने पहुंचकर आरोपी की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी अपने घर से फरार हो गया है जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसके संबंधित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

शादी समारोह में हुई थी दोस्ती, फिर प्यार

हजीरा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती से लक्कड़ खान कम्पू थाना निवासी आरोपी शान खां की दोस्ती साल 2023 में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। दोस्ती गहरी हुई, तो शान ने प्यार का इजहार कर शादी करने को कहा। युवती भी तैयार हो गई। जनवरी 2023 में शान ने युवती को मिलने के लिए बहोड़ापुर सदाशिव नगर बुलाया। मिलने पहुंची युवती को आरोपी एक दोस्त के कमरे पर ले गया और शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं लिव-इन रिलेशनशिप में रहकर उसका दो साल तक शारीरिक शोषण भी करता रहा। युवती जब भी उससे शादी करने को कहती, वह जल्द ही करने का कहकर टाल देता। जब युवती ने दबाव बनाया, तो वह शादी करने से साफ मुकर गया और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा शादी के लिए कहा तो उसे जान से खत्म कर



देगा। शोषण का शिकार पीड़िता थाने पहुंची और मामले की शिकायत की।

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

बहोड़ापुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि एक युवती के साथ उसका प्रेमी शादी का झांसा देकर दो साल से दुष्कर्म कर रहा था। युवती ने जब शादी का जवाब बनाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। पीड़ित युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।



आमजन से मिले; सिग्नल पर रेड लाइट देखकर रोकी गाड़ी

अचानक बिना काफिले के फल लेने न्यू मार्केट पहुंचे सीएम

न्यूज क्राइम फाइल

सीएम डॉ. मोहन यादव गुरुवार रात अचानक न्यू मार्केट में फल खरीदने पहुंच गए। उन्होंने बाजार में आम जनता से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम ने ठेले वालों से बातचीत की और उनके व्यवसाय के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने एक ठेले वाले से फल खरीदे और भुगतान डिजिटल माध्यम से किया।

बाजार में सीएम को देख चौंके लोग

सीएम को अचानक बाजार में देख लोगों को उनकी सादगी पसंद आई। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके मुख्यमंत्री इतनी सहजता से उनके बीच खड़े हैं। अचानक सीएम को अपने बीच में देखकर लोग अचंभित नजर आए।

काफिले में नहीं, सिर्फ दो गाड़ियों से पहुंचे न्यू मार्केट

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सादगी के साथ सिर्फ दो वाहनों में बाजार पहुंचे और 15 मिनट रुक कर फल खरीदे और निवास लौट गए।

ट्रैफिक सिग्नल का किया पालन

आमतौर पर सीएम का काफिला जिस रूट से गुजरता है। अमूमन 10-15 मिनट पहले पुलिस उस रूट पर ट्रैफिक रोक देती है लेकिन, सीएम ने अपने दौरे की किसी को जानकारी नहीं दी। वे जब फल लेकर वापस सीएम हाउस की तरफ जाने लगे तो सिग्नल पर रेड लाइट देखकर उनकी गाड़ी रुक गई। सीएम ने सिग्नल पर ट्रैफिक नहीं रोकने दिया। बल्कि, ग्रीन सिग्नल होने पर ही वे आगे बढ़े। इस दौरान लोगों ने सीएम का यह अंदाज देख वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया।



ईडी की उज्जैन और इंदौर में कार्रवाई; आय से अधिक संपत्ति मामले में एक्शन

पूर्व ईपीएफओ अधिकारी की 50 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क



न्यूज क्राइम फाइल

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भोपाल टीम ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पूर्व प्रवर्तन अधिकारी श्यामलाल अखंड और सहयोगियों की आवासीय और कृषि भूमि कुर्क की है। उज्जैन और इंदौर स्थित इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। ये कार्रवाई आय से अधिक आमदनी

के मामले में की गई है। ईडी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि अखंड और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच की जा रही है। इसी सिलसिले में 8 जुलाई को उज्जैन के नलवा गांव स्थित कृषि भूमि और इंदौर के जख्या में एमरॉल्ड सिटी स्थित एक आवासीय भूखंड को कुर्क किया है। अखंड ने अवैध रूप से अर्जित आय का उपयोग स्वयं, अपनी पत्नी और बेटे के नाम

पर अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया है। कुर्की की यह कार्रवाई पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है।

दस साल में बनाई आय से अधिक संपत्ति

ईडी अधिकारियों के मुताबिक, ईपीएफओ में नौकरी करते हुए 2009 से 2019 के दौरान अखंड ने वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति बनाई है। इसके अतिरिक्त कई पारिवारिक बैंक खातों में नकदी भी जमा पाई गई। इसके लिए उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। जांच से पता चला है कि वह रिश्तत मांगने जैसे भ्रष्ट आचरण में लिस थे।

आय का स्रोत वेतन, किराया, खेती को बताया

जांच में यह बात भी सामने आई है कि अखंड ने अपने वेतन, किराए की कमाई, खेती से आय, पत्नी के कढ़ाई और सिलाई व्यवसाय को आय का स्रोत बताया है। हालांकि, वे इसके दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर पाए। ईडी ने श्यामलाल अखंड के खिलाफ सीबीआई, ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। एक एफआईआर रिश्तत लेने जबकि दूसरी एफआईआर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के लिए की गई थी।

छह साल पहले सीबीआई ने की थी कार्यवाही

छह साल पहले सीबीआई द्वारा अखंड के खिलाफ की गई छापेमारी की कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि उन्होंने मंदसौर की साईं कंस्ट्रक्शन कंपनी से पीएफ की गड़बड़ी को दबाने के नाम पर 5 लाख रुपए की रिश्तत मांगी थी। अखंड तब उज्जैन के भरतपुरी स्थित भविष्य निधि कार्यालय में पदस्थ थे। उन्होंने दो लाख रुपए लेकर कंपनी के व्यक्ति को अपने घर बुलाया था।

पीरियड्स की जांच के लिए कपड़े उतरवाए

महाराष्ट्र के स्कूल में 5वीं से 10वीं तक की बच्चियों के साथ हरकत, प्रिंसिपल हिरासत में



पीरियड्स के बाद स्कूल छोड़ देती हैं लड़कियां- एनआईसीईएफ

2019 के एनआईसीईएफ के सर्वे में पाया गया कि देश में हर साल 2.3 करोड़ लड़कियां पीरियड्स शुरू होते ही स्कूल छोड़ देती हैं। यही वजह है कि हर साल 10 करोड़ लड़कियों की शादी कच्ची उम्र में कर दी जाती है। जबकि इस उम्र में करीब 54 प्रतिशत लड़कियां एनीमिक होती हैं। इनमें छोटे शहरों और गांवों में रहने वाली लड़कियों की संख्या ज्यादा है।

संदीप कुमार सिंह

महाराष्ट्र के ठाणे के एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 5 से 10 तक की बच्चियों के कपड़े उतरवाकर चेकिंग की गई। बच्चियों ने अपने

पेरेंट्स को बताया कि स्कूल के टॉयलेट में खून के धब्बे मिले थे। जिसके बाद सभी लड़कियों को कन्वेंशन हॉल में बुलाया गया और प्रोजेक्टर पर इसकी तस्वीरें दिखाई गईं। इसके बाद लड़कियों से पूछा गया कि किस-किस को अभी पीरियड्स हो रहे हैं। जिन लड़कियों ने हां

में जवाब दिया, उनकी उंगलियों के निशान लिए गए। जिन लड़कियों ने न में जवाब दिया, उन्हें बारी-बारी से टॉयलेट में ले जाकर एक एक के कपड़े उतरवाकर प्राइवेट पार्ट्स की जांच की गई। पेरेंट्स की शिकायत के बाद पुलिस ने प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है।

पेरेंट्स ने स्कूल में हंगामा किया

जब बच्चियों ने ये बात घर जाकर पेरेंट्स को बताई तो पेरेंट्स स्कूल के बाहर जमा हो गए और हंगामा किया। वे प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है और शहापुर पुलिस स्टेशन ले गई है। स्कूल की तरफ से वकील अभय पितळे स्कूल पहुंचे थे, लेकिन अभिभावकों ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। अभिभावकों ने वकील को घेर लिया और उनकी पिटाई करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से वे बच गए। पुलिस ने प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस आगे की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है।

शिक्षा मंत्रालय जारी कर चुका है पीरियड्स अवेयरनेस की एडवाइजरी

पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने बोर्ड एग्जाम के दौरान स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम्स के दौरान जिन गर्ल्स स्टूडेंट्स को पीरियड्स हों उनके लिए फ्री सैनेटरी नैपकिन रखे जाने चाहिए। इसके अलावा, एग्जाम के दौरान उन्हें जरूरत पड़ने पर ब्रेक मिलना चाहिए और एग्जामिनेशन सेंटर्स पर रेस्टरूम होने चाहिए।

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा: चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र मानें

न्यूज क्राइम फाइल

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन जारी रखने की अनुमति दी। अदालत ने इसे संवैधानिक जिम्मेदारी बताया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर सवाल उठाए। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में स्ट्रुक्चर के दौरान आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माना जाए। बेंच के मुताबिक, 10 विपक्षी दलों के नेताओं समेत किसी भी याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक की मांग नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर चुनाव आयोग से 21 जुलाई तक जवाब मांगा। अगली सुनवाई 28



जुलाई के लिए तय की। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी वोटर लिस्ट रिवीजन पर अदालत में करीब 3 घंटे सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियमों को

दरकिनार कर दिया जा रहा है। वोटर की नागरिकता जांची जा रही है। ये कानून के खिलाफ है। SIR के खिलाफ राजद सांसद मनोज झा, झरख सांसद महुआ मोइत्रा समेत 11

लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वकील गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की। चुनाव आयोग की पैरवी पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह ने की।

याचिकाकर्ता के वकील: अब जबकि चुनाव कुछ ही महीनों दूर हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि वह पूरी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 30 दिनों में करेगा।

सुप्रीम कोर्ट: प्रक्रिया में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह आगामी चुनाव से कई महीने पहले ही कर ली जानी चाहिए थी। भारत में मतदाता बनने के लिए नागरिकता की जांच करना आवश्यक है, जो संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत आता है। चुनाव आयोग जो कर रहा है, वह संविधान के तहत अनिवार्य है और इस तरह की पिछली प्रक्रिया 2003 में की गई थी।